किसी अच्छे काम की शुरूआत के लिए कोई भी वक्त बुरा नहीं होता।

– अज्ञात

दिल की बीमारी का प्रकोप

गांवों के 85.9 और शहरों के 80.9 प्रतिशत लोगों के पास कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है और केवल 13 पर्सेंट लोग सरकारी योजना के तहत बीमा का लाभ ले रहे हैं। यह सर्वे बताता है कि हेल्थ आज भी हमारे यहां एक बड़ी सामाजिक–आर्थिक समस्या है।

राधा शर्मा

देश में सबसे ज्यादा लोग अभी इन्फेक्शन यानी संक्रमण से बीमार हो रहे हैं, और यह बात सिर्फ ठंड में होने वाले सर्दी–जुकाम को लेकर नहीं कही जा रही। विभिन्न संक्रमणों की चपेट में आने वालों का हिस्सा ग्रामीण और शहरी इलाकों में लगभग एक सा है, लेकिन दिल की बीमारी का प्रकोप शहरों में कहीं ज्यादा है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) की ताजा रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है।

इसके अनुसार 1000 में से 29 भारतीय हर साल सिर्फ संक्रमण से होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होते हैं और इनमें पुरुषों से ज्यादा महिलाएं होती हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो शहरी और ग्रामीण दोनों को समान रूप से हो रही हैं, जैसे सांस की बीमारी। इससे देश में वायु प्रदूषण का भी अंदाजा मिलता है। हृदय संबंधी रोग 21.9 प्रतिशत शहरी लोगों को होते हैं जबकि गांवों में ये बीमारियां 13.8 फीसदी लोगों को ही होती हैं। रही बात बीमार होने की आशंका की तो शहरी लोगों में यह ज्यादा रहती है। सर्वे में शहरों के 9.1 फीसदी जबकि गांवों के 6.8 प्रतिशत लोग बीमार पाए गए।

बहरहाल, गांव हो या शहर, भारत के सार्वजनिक चिकित्सा ढांचे का हाल ऐसा ही है कि सात गुने खर्च के बावजूद लोगबाग हर जगह प्राइवेट अस्पतालों को ही प्राथमिकता देते हैं। गांवों के 85.9 और शहरों के 80.9 प्रतिशत लोगों के पास कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है और केवल 13 पर्सेंट लोग सरकारी योजना के तहत बीमा का लाभ ले रहे हैं। यह सर्वे बताता है कि हेल्थ आज भी हमारे यहां एक बड़ी सामाजिक–आर्थिक समस्या है। एक गरीब व्यक्ति अपनी या अपने किसी परिजन की बीमारी से जूझते हुए दाने–दाने को मोहताज हो जाता है। एक अध्ययन के मुताबिक एक साल में देश के करीब साढ़े 5 करोड़ लोग स्वास्थ्य पर भारी खर्च की वजह से आर्थिक तंगी के शिकार हो गए जबकि 3 करोड़ 80 लाख लोग दवाइयों का खर्च उठाते–उठाते गरीबी रेखा के नीचे पहुंच गए। सरकारी अस्पताल आज भी कई बीमारियों का इलाज करने में सक्षम नहीं हैं।

ऐसे में लोगों को प्राइवेट अस्पतालों की शरण लेनी पड़ती है जहां उन्हें कड़ी चपत लगती है। सरकार ने अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सक्षम बनाने और अस्पतालों को सुविधाओं से लैस करने के बजाय बीमा योजनाओं के जरिए निजी क्षेत्र को ही मजबूती दी है। लेकिन जिनका स्वास्थ्य बीमा है, उन्हें भी इसका लाभ अस्पताल में भर्ती होने पर ही मिल पाता है। इसके अलावा उनका काफी ज्यादा खर्च और जोखिम मामूली बीमारियों से जुड़ा है, जो बीमा के दायरे में नहीं आतीं। यह सचमुच दुखद है कि स्वास्थ्य हमारे यहां सिर्फ मैनिफेस्टो का मुद्दा है। चुनाव के समय इससे जुड़े बड़े–बड़े वादे किए जाते हैं, फिर लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। विकसित क्या, एक सभ्य देश बनने के लिए भी हमें यह व्यवस्था करनी होगी कि लोग छोटी–छोटी बीमारियों में तबाह न हों।

भविष्य के बुद्ध

धर्म-दर्शन

मनमोहन। ध्यान का अभ्यास करने वाला व्यक्ति वो कमल का फूल है जो खिलने की प्रक्रिया में है। बुद्ध पूरी तरह से खिले हुए, सुंदर और तरोताजा मानव पुष्प हैं। हम सभी भविष्य के बुद्ध हैं। इसलिए अभ्यास केंद्रों में जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, वो अपनी हथेलियों से एक कमल बनाते हैं और झुक कर एक दूसरे को प्रणाम करते हैंरू ष्आप के लिए एक कमल, भविष्य के बुद्ध। वो "आप के लिए एक कमल" कहते हुए श्वास अंदर खींचते हैं और मुस्कुराते हुए, "भविष्य के बुद्ध" कहते हुए श्वास बाहर छोड़ते हैं, तो वे खिलते हुए कमल की तरह दिखते हैं।

आप के लिए एक शिक्षक के बिना अपने दम पर ध्यान लगाना संभव हो सकता है। परंतु ये कहना आवश्यक नहीं है कि एक शिक्षक और एक संघा के साथ अभ्यास करना अधिक उचित और आसान है। एक शिक्षक के पास अभ्यास का अनुभव होता है, और वो इसमें सफल हो चुका होता है।

संपादकीय

गैर–राजनीतिक सिलेब्रिटीज

लोकसभा चुनाव में गैर–राजनीतिक सिलेब्रिटीज को सीधे चुनाव में उतार देना भारतीय राजनीति का एक ट्रेंड बन गया है। इस बार शुरू में यह थोड़ा कमजोर पड़ता लगा लेकिन समय बीतने के साथ 2019 के चुनाव में इससे जुड़े सारे रेकॉर्ड टूटते नजर आ रहे हैं। आधा चुनाव निकल जाने के बाद भी खेल और फिल्मों से सितारों को टिकट दिए जाने का सिलसिला जारी है। लगता है, राजनीतिक दलों में इतना आत्मविश्वास नहीं है कि वे अपने योग्य, समर्पित लेकिन कम चर्चित नेताओं–कार्यकर्ताओं पर दांव लगा सकें। दूसरी बात यह कि हमारा देश नायकत्व मोह से नहीं उबर पाया है। जनता इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि अनजान चेहरों को सिर्फ उनके गुणों या कामकाज के आधार पर चुन ले। अमेरिका में चुनावी प्रकिया इतनी लंबी होती है कि एकदम अनाम–सा उम्मीदवार भी वोट पड़ने तक अपनी अलग पहचान बना लेता है। लेकिन भारत में अक्सर लोग उम्मीदवार की शक्ल पहचाने बगैर ही वोट डाल आते हैं। इसीलिए राजनीतिक पार्टियां खासकर उन क्षेत्रों में, जहां उन्हें अपना पिछला प्रत्याशी बदलना होता है, ऐसा कैंडिडेट खड़ा करना चाहती हैं जिसका नाम लोगों को पता हो, भले ही उसका वास्ता कभी राजनीति के 'र' से भी न रहा हो। कारण यह कि लोग उनका नाम पहले से जान रहे होते हैं। सनी देओल से लेकर उर्मिला मातोंडकर, गौतम गंभीर और विजेंद्र तक का हाल ऐसा ही है। जाहिर है, राजनीति इनके लिए करियर की दूसरी पारी जैसी है, जहां इन्हें एंट्री बड़ी आसानी से मिल जाती है। लेकिन हाल में जितने भी सितारे संसद पहुंचे, बतौर सांसद उनके प्रदर्शन में ऐसा कुछ भी नहीं दिखा, जिससे नए सितारों के राजनीति में आने से कोई उम्मीद पैदा होती हो। कुल मिलाकर इनकी भूमिका चुनाव में किसी पार्टी को थोड़ा और कवरेज दिलाने तक ही सीमित रहती है।

ग्लोबल वार्मिंग का नकारात्मक असर नहीं होता तो हमारी इकोन०मी अभी की स्थिति से तकरीबन एक तिहाई और ज्यादा मजबूत होती। साफ है कि हमें वातावरण का संतुलन बिगाड़ने की कीमत चुकानी पड़ रही है।

वातावरण का संतुलन

अनुप जोशी

ग्लोबल वार्मिंग से हो रहा जलवायु परिवर्तन दुनिया के सामाजिक–आर्थिक विकास पर गहरा असर डाल रहा है। बीती आधी सदी में इसके कारण धनी देश और भी धनी तथा गरीब देश और गरीब होते गए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को इसके चलते 31 फीसदी का नुकसान हुआ है। यानी ग्लोबल वार्मिंग का नकारात्मक असर नहीं होता तो हमारी इकोनॉमी अभी की स्थिति से तकरीबन एक तिहाई और ज्यादा मजबूत होती। साफ है कि हमें वातावरण का संतुलन बिगाड़ने की कीमत चुकानी पड़ रही है। इस बदलाव का खाका स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में खींचा है, जो अमेरिका के प्रतिष्ठित रिसर्च जर्नल 'प्रोसीडिंग्स ऑफ दि नैशनल अकैडमी ऑफ साइंसेज' (पीएनएएस) में प्रकाशित हुआ है।

इसके मुताबिक सूडान को 36 फीसदी, नाइजीरिया को 29, इंडोनेशिया को 27 और ब्राजील को 25 पर्सेंट का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1961 से 2010 के बीच विभिन्न देशों के बीच पैदा हुई कुल आर्थिक असमानता के एक चौथाई हिस्से की वजह मानव गतिविधियों से हो रही ग्लोबल वार्मिंग ही

है। इस अध्ययन में एक तरफ यह देखा गया कि जलवायु परिवर्तन के कारण किस देश का तापमान कितना बढ़ा, फिर यह आकलन किया गया कि ऐसा न होता तो आर्थिक उत्पादन कितना होता। इस तरह पिछले 50 वर्षों में 165 देशों के बढ़ते तापमान और जीडीपी के रिश्तों का हिसाब लगाया गया। दिलचस्प बात यह कि ग्लोबल वार्मिंग से जिन ठंडे देशों का तापमान बढ़ा है, उन्हें इसका लाभ भी हुआ है। जैसे नॉर्वे का तापमान बढ़कर मानक तापमान के करीब हुआ तो उसे इसका फायदा बढ़ी ग्रोथ रेट के रूप में मिला। इसके उलट भारत जैसे गर्म मुल्क का तापमान बढ़ने की कीमत उसे आर्थिक नुकसान के रूप में चुकानी पड़ रही है। बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग ने जैव विविधता पर गहरी चोट की है। करीब दस लाख प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई हैं। साफ हवा, शुद्ध पेयजल, कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाले वनों, परागण में सहायक कीड़ों, प्रोटीन से भरपूर मछलियों और तूफान रोकने वाले मैंग्रोव्स की कमी से उनका जीवन खतरे में पड़ गया है।

यह बात संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट 'यूएन असेसमेंट ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर ऑन दि स्टेट ऑफ नेचर' में कही गई है। 130 देशों के प्रतिनिधि 29 अप्रैल से पेरिस में होने वाले सम्मेलन में इस पर विचार करेंगे। रिपोर्ट तैयार करने वाली समिति के प्रमुख रॉबर्ट वाटसन का कहना है कि भोजन और ऊर्जा का उत्पादन हम जिस तरीके से कर रहे हैं, उससे प्रकृति को भारी नुकसान पहुंच रहा है। जंगलों की कटाई, खेती और पशुपालन ग्रीनहाउस गैसों के एक तिहाई उत्सर्जन के लिए जवाबदेह है, जिससे इको सिस्टम संकट में आ गया है। जाहिर है, पूरी दुनिया साथ आकर ही इसे रोकने के लिए कुछ कर सकती है। आज जब अमेरिका जैसे शीर्ष उत्सर्जक देश ने इस मुद्दे पर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है, तब हालात बेकाबू होने से पहले उसका रवैया बदलने की प्रार्थना ही की जा सकती है।

अष्टयोग-4899

4		1	6		5	
	27	7	32		34	2
	3	2		5	7	
	37	6	33		29	3
	5			1		4
3	33	5	31	7	34	
1		4		2		6

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है. खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं. गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों और के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी. सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 4898 का हल

1	3	2	4	5	7	6
2	25	7	32	4	36	2
7	2	1	6	3	5	4
3	31	6	32	6	33	5
4	5	3	6	1	2	7
5	37	5	31	7	30	3
6	5	4	3	2	7	1

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

भयाक्रांत होने की आवश्यकता नहीं आबादी के सर्वे पर!

लिमटी खरे। आर्टिकल 370 के बाद जम्मू एवं काश्मीर राज्यों का विखंडन एवं पुर्नगठन फिर नागरिकता संशोधन कानून के बाद अब नेशनल पापुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) को लेकर देश भर में जमकर बहस छिड़ी दिख रही है। एनपीआर को लोग एनआरसी (नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन) और नागरिकता संशोधन कानून से जोड़कर भी देख रहे हैं। इसको लेकर तरह तरह के भ्रम और अफवाहें सोशल मीडिया पर पसरी दिख रही हैं, जबकि एनपीआर को बहुत ही सामान्य शब्दों में समझा जा सकता है कि यह भारत में रह रहे लोगों की रिहाईश को सरकारी रिकार्ड में दर्ज किए जाने से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। ब्रितानी हुकूमत के दौर में भी इस काम को किया जाता था, पर तब इसको जनगणना और जातिगत जनगणना के रूप में किया जाता था। विडम्बना ही कही जाएगी कि हुक्मरानों और विपक्ष के द्वारा स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट नहीं किए जाने से भ्रम की स्थिति बन रही है। जितना विरोध अभी देखने को मिल रहा है उतना विरोध इसके पहले शायद ही कभी देखने को मिला हो।